



YKKS Dharmik Samiti

Lk-, p-vkj -vkbz

Tkurkfd i fyl dsfy,

दिल्ली
पंचिका



श्री के.के. शर्मा

lpdgk vlg vcky k ds i fyl dfe'uj Jh dsds 'kel l smuds dk; dkjy ds nljku vukko fd;s x;s i fyl ak dsfodklu ejkads ckjs ea muds sopljk dh tkudkjh ds fy, thur efyd }jkj mul sfy, x, lk[krdkj dsvakA

सर, कृपया संक्षेप में अपने कार्यकाल तथा नियुक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें? साथ ही, यह भी बताएं कि पुलिस बल के एक अधिकारी के रूप में किसी सीमित दायित्व को पूरा करना किस प्रकार दो शहरों के पुलिस बल के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी से किस प्रकार भिन्न है?

मैं, d ouLifrK था tkfd fjl pl djrs gq] 1986 ea Hkjrh; ifyl l sk eal fefyr gksx; k vlg ej-sqfj; k lk dMj fn; k x; kA , l-i-h ds : lk ea 1990899 ea ukjuky] dsky] dq {k-} ikuhi r vlg jkgrd ftyleadk; Hkj l MkykA bl è 92894 dk l e; iatk vlg bl ds cMj ds {k-ka ej fo'kdkj dsky vlg dq d{k-} eavkradokn i cy FKA fdl h Hkj vkrdh geys ds ckn i fyl ea turk dk fo'okl oki l ykuk vlg i fyl dfe, ka ds eukcy dks c_lkuk l cl s cMh pukf h gpk djrsfkA , seab/ftya , df-r djuk l cl s egro iwk glk k Fkk vlg bl dk ey vkl/kkj turk dk fo'okl thruk FKA ; g cgn l rV iku djus okyk है fd ge turk dsl g; lk l s; g सब dj i trsfka

bl ds vykok मैंने bLiDvj tujy vkl i fyl ds: i, ea bLiDvj tujy vkl i fyl v/ kkl u/rFkk nf{k.k jst t s egro iwk पढ़ों पर dk; Hkj l Mkyk gk orkku esipdgk o vcky k ds dfe'uj ds: i es dk; jk jk , d 0; fdr dksvius

vf/kdkj {k- ea vokus okys fofofklu ft ykadsfy, vi usy{; vlg edl n dksfuf'pr djds ; g l fuf'pr djuk होता है fd ; fuV ds l Hkj [km l gf0; rk vlg l kefL; l skde djarkfd fuf'pr y{; dksidr fd;k tk l dA nlijs 'knka ej ; g , d nli?kf; ltu dk Lrj gstdcf fd vxj fdh dks, d fo'ksk dke fn; k tkk gS rkj ml s dso fuFu fu; ltu djuk glk gS rkfd edl n dksdkum dsnk; js eajgrsqq ijkf; dtk l dA

'जाँच' करना 'कानून व्यवस्था' सम्मालने से बिल्कुल भिन्न है इसलिए जाँच में प्रचलित प्रक्रियाओं बल्कि प्रचलित और कानूनी तरीकों के बारे में अपने विचारों से अवगत करायें। क्या 'इन्हांस इवेस्टीगेशन टेक्नीक' या 'थर्ड डिग्री' का उपयोग सच्चाई का पता लगाने में कारगर सिद्ध होता है? क्या जाँच के दौरान इन तरीकों में निहित मानवाधिकार के हनन को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है?

bl ea dkbz l ang ugh gS fd 0; oLFkxr oKkud tkp rduhdkadk mi; lk vnkry ea tkp ds l k{; ds : i ea cgn c+<tkt gk gk ykfd] bl rF; l s Hkj bdkj ugha fd;k t k tk l drk fd Hkj r ea gekj i kl vi sfskr Lrj ij ; g mi yCk ughgk gk ve kt Hkj mlufr/khy nsk gk vlg ; gk l d k kuka dh l eL; k gk fQj Hkj i fyl 'g ds fy, ctV dk fu; ltu dj i fyl ak dsbl i gywldksolkfkr egro fn; k tkuk pkf, u fd bl ds [kPkdksvfu; ktr Jskh eaj [k tkna चाहि, A

I kfk ghk gekjs; gk tkp dslrj ea l k jk ds fy, rduhdkh fo'kdkj Krk dh vo/kj. lk dksv Hkj l k kxr fd;k tkuk ckdh gk tcf] bl rduhdkh fo'kdkj Krk dh dkbz deh ughgk tkp ea i kye tkusokys vkerig ij l Hkj i dkj ds njkpkj, Hkj vlg i kikr dsdkj. k gk; k fQj 0; fdrxr ykyp] vi ; klr l Efk; ; k i fjk .ke i kus ea 'k?krk dsdkj. k glksgk tks Hkj gk ekouf/kdkj l Ekl/kh ejka dksutjvlnkt djuk fd l Hkj : i esu; k; l ar ughgSD; kdk i fyl dh udkj Red Nfo dk

, d i fyl vf/kdkjh dsl e{k dh xbz xqk gk dcyh vnkry ea ek; ughgk t] . tfVy vlg ych i f0; k, a ej ; : lk l svijk/kadnsntzu gk usdsfy, rFkk ycsedneka

el; dkj.k; g gk gk

पुलिसिंग के काम को योजनाबद्ध करते हुए प्राथमिकता किसे दी जाती है — 'कानून—व्यवस्था' कायम रखने को या फिर 'जाँच' के काम को? क्या आपके विचार में जाँचटीम और कानून—व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस की टीम अलग होनी चाहिए?

fcl h Hkj {k- eadkum&0; oLFkk dk; e j [kuk gesk gh tkp ij i kfkfedrk j [krk gSdoy , d h i fjkFLFkr; ka dks NklMdj tgk tkp u gk us dh FLFkr ea ; k dkbz l jkx u feyus dh FLFkr ds dkj.k dku&0; oLFkk ea xMeMh dsgkykr i Shk gk st, k tc 'kkr dk ekglk gk gsrc tkp i kfkfedrk ij gk gk gk dku&0; oLFkk vlg tkp ds fy, fuf'pr : i l s vyx 'kk [kRsgkuh pkf, A

क्या आपके विचार में आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, शिक्षयतक्ता के लिए न्याय प्राप्त करने में अड़चन पैदा करता है?

ejfopk jkjk e;a; g , d fefkd gk ykfd kdk, d k yxrk gS tcf d , d k gk ugha gk ykfd vI kfk tdk rkoaksI kfk dBlkj gk us dh vuifpr ugha l e>k tkuk pkf, u gh bl svkjkh dskuotf/kdkj dh gk guu l e>uk pkf, A

आपके विचार में कोई कमी है जिस कारण पुलिसकर्मी सही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं? पुलिसिंग की आंतरिक समस्याएं क्या हैं?

gk ekuo }jkj cuk, x, dkuw vpcd gk, d k ddkh ughgk gk vlg bl fy, i fjkFLFkr; ka ds vuj kj bl eayxkrj l k kuku dh vlo'; drk gk gk dke i j yxs fdh i fyl vf/kdkjh ds fy, fuEufyf[kr i fjkFLFkr; k cgn dfBu gk gk gk

, d i fyl vf/kdkjh dsl e{k dh xbz xqk gk dcyh vnkry ea ek; ughgk t] .

शेष भाग पृष्ठ 2 पर.....

cwlsvkS thir" &8

प्रिय पाठकों,
यहां i fyl पवित्रा द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतियार्थी की सुरक्षात जनवरी 2012 से की गई थी। इसके अंतर्गत आपके केवल 5 सालों पूछे जाते हैं, जो आपके काम से सम्बन्धित होते हैं। सही जवाब भेजने वाले 2 विजेताओं को 500 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया गया है। यहां आपको जाना परिक्रमा के प्रकारित दिये जाते हैं। आगे सही जवाब भेजने वाला कोई एक ही व्यक्ति है जो केवल उनका ही नाम प्रकाशित किया जाता है। आसा है आपको अधिक संख्या में इसमें भाग लेने रहें।

आपके समाज निम्नलिखित हैं:-

- बच्चों के बलात्कार की जाँच किसने दिनों में पूछी होती चाहिए और यह व्यक्ति किस प्रावधान के अंतर्गत ताकी नहीं है?
- क्या पुलिस किसी के घर की गाई है?
- क्या रास्ते में रोक कर पुलिस नाम व पता करी ही पूछ सकती है? क्या इंकार करने पर पुलिस को गिरफ्तारी करने का अधिकार भी है?
- क्या किसी गहिरा को लिए ऐसे देकर खारेदान अपराध है? यदि 'हाँ' तो किस कानून के अंतर्गत।
- अगर परवैदान पुलिस उपलब्ध न हो तो क्या किस विवाहीन कीटी को शारीरिक रूप से अवालम में प्रस्तुत किये बर्बाद कुदरतों की सुरक्षा हो सकती है? क्या मुद्रणों की प्रत्येक तारीख पर आरोपी का अवालम भौज द्वारा बाधित है?

हुई ओर जीतो — 5 का परिणाम

नई 2012 अंक का परिणाम इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और जिजेता का नाम निम्नलिखित है।

- दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 162 के अंतर्गत पुलिस को जाँच के दौरान दिये गये बयान पर हताहार करना आवश्यक नहीं है।
- दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 210(2) व धारा 41(2) के अंतर्गत पुलिस असंघय अपराध में वारंट के बरेर गिरफ्तारी नहीं कर सकती है।

3- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 43 के अंतर्गत कोई आम आरोपी नहीं करना चाहिए व अपनाती अपराध करते हुए देखे गए वा वह कोई उच्चारित आपराधी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

4- हाँ, चार्जराईट व अंतिम रिपोर्ट एक ही दस्तावेज का कहा जाता है। यह दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस द्वारा प्राप्तिक जाँच के आधार पर दायर की जाती है।

5- किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी द्वारा एक पर्याप्त भारा आरोपी के वज़ावाती अपराध करते हुए देखे गए वा वह कोई उच्चारित आपराधी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

4- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 43 के अंतर्गत कोई आम आरोपी नहीं करना चाहिए व अपनाती अपराध करते हुए देखे गए वा वह कोई उच्चारित आपराधी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

5- किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी द्वारा एक पर्याप्त भारा आरोपी के वज़ावाती अपराध करते हुए देखे गए वा वह कोई उच्चारित आपराधी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

6- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 43 के अंतर्गत कोई आम आरोपी नहीं करना चाहिए व अपनाती अपराध करते हुए देखे गए वा वह कोई उच्चारित आपराधी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

7- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत पुलिस असंघय अपराध में उच्चारित आपराधी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

8- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

9- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

10- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

11- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

12- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

13- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

14- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

15- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

16- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

17- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

18- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

19- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

20- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

21- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

22- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

23- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

24- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

25- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

26- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

27- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

28- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

29- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

30- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

31- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

32- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

33- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

34- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

35- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

36- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

37- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

38- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

39- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

40- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

41- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

42- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

43- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

44- हाँ, दब्ज प्रक्रिया सहिता की धारा 41(2) के अंतर्गत आरोपी को देखे तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है।

vkRefodkl

ifyl dk; z u døy tfly
i qfr dk gScfVd ; g 'kjifjd
o elufl d : i ls Fdk nsus
okyl tk [ke Hkjg gA bl dsfy,
ifyl dehcls 'kjij o elufl d
nkuks l sLoLFk jguk t : jh gA
mi ; Qr [kkui ku] 0; k; ke]
vkjke, o LoLFk euijkatu ls
bl sgkf y fd; k tk l drk gA
bl gqf fuetu ckrks ij /; ku
nsuk t : jh gA
1½ ifyl dk; z es vDl j
vfu; fer oDr ij M; Wh jgrh
gS ft l es cktkj dh ryh&Hqj
oLrq tS sl ekd k feBkbz vKfn
[kkusRfk vr; f/kd pk; @dkQh
i hus dh i qfr jgrh gStksol k
vkj phuh ds dkj.k 'kjij ds
fy, gkfudkj d gkrs gA , ds
vol jka ij puu ejxQyH Qy
vKfn yusplkg, A
1½ fu; fer [kkus es Hh MkYmk
dh txg l j l is; k l ks kchu dk
ry mi ; kch gA
1½ pk;] BwMsis vKfn dsLFkku
ij 'kjij ty dghavPNk gA jkst
688 fxykl ikuh dk l ou
yHmk; d crk; k tkrk gA
1½ ol k jfgr nuk eVBlj ngh
dk fu; fer l ou LoLFk qfsg; Y

ds fy, d^yf'k; e mi y^ck
 djkrk g^A
 15½ Fkdkl&Fkdkl H^cstu vusd
 ckj djuk vf/kd LokLF; dj g^A
 16½ ued vlg phuh dk de I s
 de i^z kx^c djuk plfg, A
 17½ 0; k; ke i e^ck : i I s rhu
 i dkj ds gkrs g^c& jDr l plkj
 c<kus okys rkdr c<kus okys
 rFkk yphyki u (Flexibility)
 c<kus okys rhuls gh vPNs
 LokLF; dsfy, t: jh g^A
 18½ jDr l plkj c<kus okys
 0; k; ke g^c& rst pyuk nk^cuk
 19½ xfr I s ; k rst½ rjuk
 vlfnA bues l kd Qwys yxrh
 g^A Q/c^cly] gkdij cld^cckly]
 c^clfed^cu] Vsul Hh bI Jst h es
 vkrsg^A ef[; ckr gSgfk i^cka
 dk l plkyuA, s 0; k; ke
 i frfnu de I sde 40&50 feuV
 rd fd; s tkus plfg,] plgs
 15&15 feuV ds rhu H^cks es^A
 , d gh LFku ij dnerky ; k
 t^clfx^c I s Hh i ; k^cr yHk fey
 l drk g^A
 19½ rkdr c<kus ds 0; k; ke ea
 I cl svkl ku vlg l gyHk n.M o
 cBd g^A o^c fyQfV^cak M^ccy]
 ; k fte e'ku ea Hh rkdr

c<kus olys 0; k; ke glos gä
bul s eld iſ'k; ka rls etcw
gkrh gh gþ gfMMf ka dk Hh
(kj .k gkusi scprk gä búgarhu
Hkoks es 20&20 cjk djuk
pkfg,] ; k tc rd eld iſ'k; ka
Fkl u tk; A
1/10% yphysiu dsfy, ; lskl uj
iHOVHO 'kjhj ds foſHdu vaks
dkStrech djuk vkrn gä
1/11% Hkstu ds rjür ckn dks
NkMrssq 0; k; ke dHh Hh fd; k
tkl drk gä
1/12% ekufi d LokLF; ds fy,
I cl svko'; d gſthou dsifr
I dkjlkRed nſ'VdklKA chrh
cirk i j I e; xokusdsctk;
vloksch l kpuk bl dk , d eſ;
Hkox gä
1/13% iſyl dk; Zeal ekt ds
foſHdu oxk! Isesy&tky dk
vPNk eldk jgrk gþ bl dk
Qk; nk mBkdl l kelftd : i ls
I fØ; jguk pkfg,A bl ls u
døy ekufi d o HkoulRed
LokLF; vſtř glokl cfvd
iſyl dk; Zeal Hh bl ls enn
seyxhA
1/14% i<ukl fy[luk vlg euu
diuk eſlr" d dsfv, mruk ah

t : jh gSftruk 0; k; ke 'kjh
dsfy, A
1/15½ [kjy dm esHkk yusl seu
vkj 'kjhj nkuka dks ylk
igprk gA
1/16½ viusLokLF; dh n'lk bu
I dZdrds l si gpku I drs g%&
1/17½ tu 60&65 fd0xk0
1/17½ dej 40 bp l sde
1/17½ ek/kik vusd chekfj; kadh
tM+ gA mi; Ør Hktu vkj
0; k; ke l s bl s de fd; k tk
I drk gA
1/18½ ok'kd esMdy i jh(k.k)
fo'ksk : i l s CyMi 8kj
CyM+ lkj] dklytVt rFk us-
ijh(k.k l s vusd chekfj; ka dk
irk yx I drk gA
1/19½ rEckdw fd l h Hk : i ea
'kjhj dksHkjh upl ku i gpkrk
gA bl dh yr Ndkuk vr; r
dfBu gA
1/20½ 'kjkc dk l su Hk LokLF;
dsfy, gkfudkj d gS fo'ksk : i
l sbl dh yr i M+tkusijA

पृष्ठ 1 dk शेष

dsfy, ftEeskj gš
xogkla ds fy, dkbz fo'ksk
I jšk@i kelsku Ldhe dk u
glsuk@turk ls l cır, df=r
djusdsfy, oláksr I gk; rk ds
fy, dkum dk u gkukj
tehu ds cáloljs dks
I fuf'pr djus ds fy, fdl h
dkum dk u gkuk vlg iR; sl
cnysgq elkyd dsl lkF tuujy
ikoj vklv vVuh tgs
fooknkl in nLrost dk gkukj
vlkj
dbzds kseavijlk dsvuqkr
ea n.M de gkuk tgs & tøk
vf/fku; e ds varxlr vlfna
mijlør dsvykolj fuEufyf[kr
vkrfjd l el; k, ag%

fo'ksKrk dh vo/kj. kk dh
deh

Yxkrkj 24 ?oVlach pléll h
dsfy, vi; klr i[yl cy]
fofo/k fu; æ.k o vuqkl u
I xcfl/kr vf/kdjkj
vi; klr kóps
cxg vuqkfrd rü[okg ds
0; ki d 'kfrd vlg ftEeskjh ls
njkpkj i uirkgs vlg
yxkrkj c<sh turk dh
vi sk avlfna

i fylx ds dbz i gyw vlg
vk; ke g¹ tgk jkT; dh l j¹ lk
'kfey gks ogk, d h vklrfjd
l j¹ lk dk jkVh; Lrj ij
l Ecf¹ku gksuk pkf¹, A, d s
LFkkuk¹ dh ckuk¹&0; oLFkk dks
rjr gh, d cgn vPNs
I keatL; j [kus okyh jkVh;
fudk; }jk mi yGk I okd/kd
0; okl kf; d 0; fDr; ka}jk rc
rd l kkyk tkuk pkf¹, tc
rd flFfr i yjh rjg fu; a.k ea
u vk tk, A

dk; ZdÜkkka ds }jk ubz
mi yfc/k; kadsckj seahfM; k ds
ylokska dks Hh fu; fer : i ls
tkudkjhn tkrhga

fupysLrj ds i fyl dfez kads
vku ea cnyko ykus vlg
i fyl a eal dkj djuscsfy,
mijkdr myYkfkr ulfr Lrj ds
fu. k zedh vko'; drk qll

आपके नेतृत्व वाले शहरों में
जिला और थाना स्तर की पुलिस
द्वारा समुदाय और पुलिस के बीच
सम्बन्धों की बहतरी के लिए क्या
विशेष कदम चलाये गये हैं?

कई स्थानों पर थाना प्रभारियें
को *idk'k fl g ds d* में पुलिस
सुधार पर उच्चतम न्यायालय के
दिशा-निर्देशों के बारे में
जानकारी नहीं, क्या आपके
विवार में थाना स्तर के
पुलिसकर्मियों को इसकी
जानकारी होनी चाहिए ताकि वे
अपने लिए निश्चित कार्यकाल
आदि की मांग कर सकें? या, ये
दिशा-निर्देश पुलिस सुधार के
लिए अनावश्यक हैं?

क्या आपके विचार में आठ घण्टों के शिफ्ट सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए? क्या इससे पुलिसकर्मियों के कार्य-निष्पादन में सुधार आएगा?

अंत में, ykl i fyl के बारे में
अपने विचारों से अवगत करायें,
क्या यह पुलिसकर्मियों की
जानकारी बढ़ाने के लिए एक
लाभदायक श्रौत है?

नीति के स्तर पर कौन से क्षेत्र हैं जहाँ बदलाव की आवश्यकता है? अगर आपको बदलाव करने की खुली छूट हो तो आप पुलिस के कार्य निष्पादन को बेहतर करने के लिए किन बदलावों की सलाह देंगे?

I Hm I svjkeau; fer : I Is
LFKuh; turk ds I Kfk ehVhak
dh tkrh gS ftulgauS vi uh
, l kI , 'ku Hh cuk yh gS jkM
I jgfk I axBu tksd vi uh
tkudkfj; k ckwrsjgrsgs milga
(k- eacgrj i fyflx dsfy,
I z d7 fd: k tkrk qS ske ds

D; k vki tkursg\

इस श्रृंखला के अंतर्गत, मई के महीने से हम गृह भंत्रालय द्वारा 'साम्प्रदायिक सदभावना' से सम्बन्धित जारी दिशा-निर्देशों के कुछ अंश प्रत्येक अंक में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस श्रृंखला में यह अंतिम कड़ी है। हमने इन दिशा-निर्देशों को हमेशा ज्यों का त्वयि इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि आप इस पर अपना मत विकसित कर सकें और इनका कितना पालन आपके राज्य में दिखाई पड़ता है, हमें भी इससे अवगत करायें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।

I kei ikf; d l nhkouk i j xg eky; } kjk tljh fn' lk&funik
8- कार्यान्वयन किया और केसों की मॉनिटरिंग

8-1. जब भी किसी साम्प्रदायिक घटना का डर होता है या घटना घटती है, शीघ्र और तुरंत रोकथाम/प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य किये जा सकते हैं, जिसमें निषेधात्मक आदेश/कर्तव्य आदेश शामिल हैं, आवश्यकतानुसार इसका सख्ती और निष्पक्ष रूप से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, सम्पादित बदलाव जो आगजनी, हिंसा आदि में संलग्न हों, को पकड़ना/गिरफ्तार करना, केसों की शुरुआत करना/दर्ज करना।

8-2. साम्प्रदायिक हिंसा/दंगों से सम्बन्धित केसों की निगरानी (मॉनिटरिंग) सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो निष्पक्ष और साफ जांच को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच टीम बनाए जाने की

आवश्यकता है।

8-3. सम्बन्धित राज्य सरकार अगर चाहे तो उपरोक्त केसों के उचित अभियोजन तथा इनकी प्रबलता से सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति कर सकती है। ऐसे सभी केसों की निगरानी जिला तथा राज्य स्तर पर की जानी चाहिए।

8-4. जहाँ परिस्थिति की मांग हो, साम्प्रदायिक केसों में जल्दी मुकदमे तथा इनके शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल अदालतों की स्थापना की जा सकती है। जब कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है और इंकावायरी कमिटी/कर्मीशन की स्थापना की जाती है, इसे अपनी इंकावायरी पूरी करने के लिए एक समय सीमा दी जानी चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि वह कमिटी/कर्मीशन को उचित और आवश्यक सहायता प्रदान करे ताकि वह अपनी रिपोर्ट समय पर जामा कर सकें। इसकी सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए, तकरीबन तीन महीनों के भीतर और केन्द्र सरकार को इसके बारे में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9. राहत और पुर्णसुधार

9-1. दंगा पीड़ितों को राहत/तुरंत विरीति सहायता न मिलने से उनमें आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इस सहायता के शीघ्र संवितरण के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। साम्प्रदायिक हिंसा के कारण नुकसान सहने वाले लोगों को तुरंत अग्रिम सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

9-2. साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता और राहत पहुँचाने में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें लिंग, जाति, समुदाय, वंशज या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

9-3. जिला प्रशासन को साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं जैसे कि, खाना, दूध, दवाईयाँ, पानी और विजली आदि का इंतजाम सुनिश्चित करना चाहिए।

9-4. जब भी सहायता शिविर लगाना आवश्यक हो जाए, सुरक्षा और दूसरे आवश्यक सुविधाओं का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए, जिसमें मेडिकल जांच/सहायता आदि भी शामिल है।

9-5. रिहाईशी और व्यवसायिक सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति में अगर आवश्यक हो तो, बीमा दावों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज देने/पुनर्निवारण आदि के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र निपटारे की यंत्रावलि विकसित की जानी चाहिए।

9-6. केन्द्र सरकार ने आतंकवादी हमले तथा साम्प्रदायिक हिंसा के कारण पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत दी जानी वाली सहायता के अलावा भ्रामित व्यविधियों को, एक बार 3 लाख रुपये की सहायता देने के लिए केन्द्रीय स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए सभी इंतजाम किया जाना चाहिए।

प्रस्तुति : जीनत मलिक

vki dsfoplj

I मं knd egks; k
UreLdkj!

Vkkd i fyl ds ebz vd ea
D; k vki tkurs g* ds
varx\ r kinkf; d l nhkouk
ij xg eky; } kjk tljh
fn' lk&funik ds d\N v\k
i <tsdlsfey\ bl dstuolkj
mik; k ds varx\ ftjk
iz kkl u rFkk i fyl ds
nkf; Rok ds cljs ea egoi w\k
tkudkf; k lkr g*A
gk*f*l vkerkj ij budk
ijh rjg i kyu gk* fn[k*b
ughi M*k g* fQj H*j i fyl
ef kfcjk I s dkQh vPNh
tkudkf; k i lkr djrh g*tks
mudsck easy*kknk; d gk*
g* ysfduj vktdy mudk
fo okl i fyl ij d\N de
gk* g*k fn[k*b i M+jgk g*
bl dsckjseap*syxrk g*gea
mlga d\N i gpkui= v\kfn
nsuk pkf, v\k tks ylk
yxkrkj i fyl d*l puk nrs
jgrs g* mlga , d U; ure
fu*pr ekun\ H*n nsuk
pkf, A bl i f=dk ea , d h
tkudkf; k d*k l eko\ cgn
l jkguh; g*

/W; okn!
b*i *Vjj t*kki j
I nL;] jkt LFKku i fyl

Egks;]

gekjs Fkkus ea ykdl i fyl
i f=dk i gyh ckj n*kus dks
feyh ; g tu 2012 vd g*
bl l sigys; g gekjs; gk* ug*
igprh Fk* vi us jk*; ds
i fyl egkfun*kd I s
I k*kdkj i <edj cg* vPNk
yxk* ysfduj e* , d ckr
dguk pkgrk g*vki ylk v\k
eh*M; k gekjs jk*; ea
i fyl x ds dkeka ea
ekuof/kdkjk ds guu ds
ekeyk ds gesk* mtloj
djrs g* tcfd bl dk , d
e* ; dkj.k g*; gk* fd fo'ky
tul {; k v\k ml eadke dh
vf/kdrk dk gk*A ges H*h
ylok ds I k*k I [f*h I s i sk
vkuk vPNk ug* yxrk,
ysdu ylok dh elak ds
vu* kj t*nh d* gy djus
dsfy, dbzckj dkuu I svbks
c<uk i M*k g* ysfdu]
/kj&/kjjs , d s d* k ea deh
vk, xh D; kdk i fyl Loq H*h
, d h ckrk I s cpus yxh g*
; g ejsvi usfoplj g*vlg e*
vi uh i gpkui xk* u*; j [uk
pkgrk g*

/W; okn!

g* d*k*Vcy] ejB
m*nj i nsk i fyl

i fyl v\k Xk* kqk cPpk*sdh ryk' kh

होरीलाल नामक व्यक्ति ने अपनी गुमशुदा नाबालिंग बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट कराने के ढेढ़ साल बाद भी दिल्ली पुलिस द्वारा उसका पता लगाने में असर्वत्त्व होने पर उच्चतम न्यायालय में जनवरी 1997 में रिट याचिका दायर की। लेकिन, फिर भी कई निर्देशों के बावजूद पुलिस उसका पता लगाने में नाकाम रही। इसी दौरान 14 नवम्बर 2002 को तकरीबन 15 साल बाद सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने gjk*ly
cuje dfe'uj v*k* i fyl fn'yh o
v*l; ds d*l में गुमशुदा/अपहरित नाबालिंग बच्चियों के सक्षम उन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से दृढ़ने के लिए देश के सभी जांच अधिकारीयों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने का आदेश दिया।

1- गुमशुदा लड़की का फोटो अखबार में छपवायें, उसे तुरंत दी.की. पर प्रसारित करवायें और इसमें शिकायत समय नहीं लगाना चाहिए। गुमशुदा व्यक्ति के फोटोग्राफ का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए शाहर/गांव/टाउन सम्बन्धित रेलवे स्टेशन, अंतर्राजीय बस अड्डों, हवाई अड्डों, स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय और कानून लागू करने वाली ऐंजेसलिंग द्वारा सीमाओं के चेकपोर्ट पर तुरंत जाना चाहिए। यह तुरंत किया जाना चाहिए और शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अवश्य ही किया जाना चाहिए। लेकिन नाबालिंग/व्यस्क लड़की के गमले में अभिभावक या माता पिता के

लिखित आज्ञा के बाद ही ऐसा करना चाहिए।

2- गुमशुदा लड़की के पड़ोस में, काम/पद्धाई की जगह पर, सहेलियाँ, साथियाँ, सहकर्मियाँ, रिश्तेदारों से तुरंत पूछ-तात्क की जानी चाहिए। उसी प्रकार कागज और गुमशुदा व्यक्ति के परिवार को ग्रामीण सुराग की तुरंत जांच की जानी चाहिए।

3- गुमशुदा व्यक्ति के सबसे नये स्कूल / शैक्षणिक संस्थान के प्रिन्सिपल, क्लास टीचर को सम्पर्क करें। अगर गुमशुदा लड़की/महिला कहीं नौकरी करती थी, तो उसके सबसे नए सहकर्मियों, नियोजक, मालिक के सम्पर्क करें।

4- गुमशुदा लड़की/महिला के विशेष परिवार के रिश्तेदारों, पड़ोसियों, स्कूल टीचरों और स्कूल के दोस्तों से पूछ-तात्क करें कि क्या परिवार के लिए इन्हें चाहिए।

5- इस बाद की पूछ-तात्क करें कि क्या वर्तमान समय में लाइ गई है। इसके बाद जांच अधिकारी/एजेंसी निम्न कदम उठायेंगे:-

(क) कर्मचारीपूर्वक यह सुनिश्चित करेंगे कि जो जानकारी माता-पिता से मांगी गई थी वह उनसे प्राप्त कर ली गई है और सुराग के लिए उसका परीक्षण करेंगे।

(ख) शिकायत मिलने के तुरंत बाद अस्पतालों और मुद्राधारों की तलाशी ली जानी चाहिए।

(ग) गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सुराग देने वाले को इनाम देने की घोषणा उसके गुम होने के एक महीने के भीतर कर देनी चाहिए।

(घ) समय से नोटिस भी गुमशुदगी के एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए।

(ङ) जहाँ तक सम्भव हो जांच, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए।

(च) सम्बन्धित पुलिस कमिशनर या राज्य पुलिस के डी.आई.जी./आई.जी. गुमशुदा लड़कियों व महिलाओं का पता लगाने के लिए एक मल्टी टास्क फोर्स की स्थापना करने की राह निकालेंगे।

(छ) साथ ही, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई जैसे महानगरों में जांच अधिकारी वैश्यावति वाले इलाकों में तुरंत इसके जांच करेंगे और नाबालिंग लड़कियों का पता लगायेंगे। अगर कोई नाबालिंग लड़की पाई जाती है (चाहे वह वर्तमान समय में लाइ गई हो या नहीं), तो उसकी आज्ञा लेकर किशोर न्याय (देव्य व रुस्ता) अधिनियम 2000 की धारा 34 के अंतर्गत उसे बाल गृह में रखा जाए। जांच अधिकारी सभी मेडीकल/अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

इसके साथ ही अदालत ने इस आदेश को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तक पहुँचाने की भी निर्देश दिया है।

इसके बावजूद, उपरोक्त दस्तावेजों का इनाम देने की घोषणा हर दिन कोई न कोई परिवार अपने बच्चे की गुमशुदगी से भ्रगतने पर मजबूर है।

प्रस्तुति : जीनत मलिक

i fyl | ekpkj & gj dksisdh gypy

100 fnuks es 0; oglj es cnyko!

उडीसा के नए डी.जी.पी. श्री प्रकाश मिश्रा ने जुलाई के पहले सप्ताह में अपना कार्यालय संभालते ही थानों में पुलिस द्वारा जनता के साथ असम्भव बर्ताव के बारे में कड़ा रवैया अपनाते हुए पुलिसकर्मियों को सुधार के लिए 100 दिनों का समय दिया है। उन्होंने कहा "मुझे 100 दिन दें और आपको इनके रुझान में अन्तर दिखेगा"। हाँलांकि, अपने दिए हुए समय सीमा के अन्दर थाना स्तर के पुलिसकर्मियों के रुझान में बदलाव लाने का क्या तरीका होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दरअसल, राज्य डी.जी.पी. द्वारा सुधार के लिए कड़ा रवैया अपनाने का कारण हाल ही में हिरासत में हुई दो कथित हत्याओं के केस के कारण भी था। 100 दिनों के भीतर पुलिसकर्मियों के आम व्यवहार में अगर साकारात्मक बदलाव आ भी जाते हैं तो भी यह पर्याप्त नहीं है। हिरासत में हत्या होने का अर्थ यह है कि पुलिसकर्मी कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुप्योग कर रहे हैं और कानूनों को तोड़ कर स्वयं अपराध कर रहे हैं, इसलिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर विभागीय और आपराधिक कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि दूसरों के लिए कठोर उदाहरण सिद्ध हो सके।

VkfstU; % VkbE1 vklD bFM; k MKW bFM; k VkbE1 MKW dklt 9 tylbz/2012%

efgyk i fyl dfeZks ds fy, i kB' klyk

चेन्नई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहाँ महिला पुलिसकर्मियों के लिए परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा ताकि उन्हें महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में पीड़िताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है और शिकायतकर्ताओं के साथ सम्बन्ध के संबंधित विवरण जाएं। दरअसल, ऐसा कहा जा रहा है कि यह आयोजन करवाने की आवश्यकता तब पहीं जब कुछ शिकायतकर्ताओं ने पूछ-ताउ और रिपोर्ट दर्ज करवाने के समय उनके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा अच्छे बर्ताव न होने की शिकायत की थी। इस प्रशिक्षण में अधिकार पुलिसकर्मी महिला थानों से होंगी क्योंकि उन्हें प्रतिदिन महिलाओं से सम्बन्धित केसों से निपटना पड़ता है। सबसे

vf/kd bu i fyl dfeZks ds fy, l dh vko'; drk gM bl fy,]

महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता को उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। समाज सेविका श्रीमति वरिष्ठी रविचंद्रन के अनुसार कांस्टेबल स्तर की महिलाएं आम तौर पर देहात के इलाकों से आती हैं जिनकी भर्ती एक लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता टेस्ट के बाद हो जाती है और उन्हें काफी कठिन काम करने पड़ते हैं। यह उनके काम के लिए काफी नहीं होता है, परामर्श सत्र उन्हें महिला पीड़ितों की मदद करने में बहुत हड़ तक कारगर हो सकता है, खासकर बलाकार पीड़ितों के केसों में। तकरीबन 50% केसों पर विश्वास नहीं किया जाता है, हमें इस रुझान को बदलना है। बड़ापालानी की एक महिला थाना कि सेवानिवृत्त महिला इंस्पेक्टर के अनुसार 'एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी कुछ ही क्षणों में केस की सत्यता के विषय में निर्णय ले सकती हैं।' जहाँ वर्तमान स्थिति में महिला पुलिसकर्मियों के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने की यह एक अच्छी कोशिश है वहाँ महिलाओं से सम्बन्धित केसों में संवेदनशीलता पूर्वक व्यवहार करना सिखाए जाने की आवश्यकता भी है।

VkfstU; % VkbE1 vklD bFM; k MKW bFM; k VkbE1 MKW dklt 19 tylbz/2012%

Ekgyk i fyl dfeZks ds fy, dkls i jw djusdh dkls k' k!

तमिलनाडु के डी.आई.जी. पुलिस श्री डी. शुक्ला ने संकेत दिया कि 2&3 महीनों में वहाँ सम्मवतः एक विशेष मर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी जिसमें महिला कांस्टेबलों के रिक्त स्थान को भरा जाएगा। श्री शुक्ला के अनुसार यह मर्ती प्रक्रिया 750 रिक्त स्थानों को भरने के लिए है, जिसमें 400 होम गार्ड, 200 इंडियन रिजर्व बटालियन और 26 जेल वार्डरों की मर्ती शामिल होगी। 22 जुलाई 2012 को हुए मर्ती टेस्ट में, अधिकारी महिला आवेदक शारीरिक योग्यता टेस्ट में असफल हो गई क्योंकि इसमें सफल होने के कठोर मानक थे। परी शारीरिक टेस्ट की प्रक्रिया को सी.सी.टी.वी. कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। कुल 1750 आवेदकों में से केवल 18 महिलाएं आवेदक ही इस टेस्ट में सफल होकर लिखित परीक्षा में भाग ले सकीं। श्री शुक्ला ने बताया कि विशेष मर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से पहले वे लोग सी.सी.टी.वी.

कैमरे में रिकॉर्ड किये गये भाग के आधार पर शारीरिक योग्यता के मापदण्डों का अकलन करेंगे।

तमिलनाडु में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसलिए यहाँ नीति पर अति शीघ्र विचार करने और इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में सफल हो सकें। लेकिन यह आवश्यकता केवल यहाँ नहीं है और उन्हें काफी कठिन काम करने पड़ते हैं। यह उनके काम के लिए काफी नहीं होता है, परामर्श सत्र उन्हें महिला पीड़ितों की मदद करने में बहुत हड़ तक कारगर हो सकता है, खासकर बलाकार पीड़ितों के केसों में। तकरीबन

VkfstU; % vkbz ch, u ykbz MKW bu MKW dklt 25 tylbz/2012%

i fyl dfeZks ds fy, gki ykbz!

महाराष्ट्र में गडचिरोली पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए 'समाधान कक्ष' नामक हेल्पलाईन की स्थापना की। इसका उद्घाटन जुलाई के अंतिम सप्ताह में वहाँ के कलेक्टर श्री अभिषेक कृष्ण द्वारा इस रेंज के डी.आई.जी. तथा एस.पी. की उपस्थिति में किया। इस शुरुआत को प्रगतिशील बताते हुए डी.आई.जी. श्री रविन्द्र कदम ने विश्वास जाताया कि पुलिसकर्मी इस सेवा का लाभ उठाएंगे। एस.पी. श्री सुवेज हक ने बताया कि 'शिकायतों को फोन पर दर्ज किया जाएगा और उसे सम्बन्धित विवाह में निपटारे के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ से इसका निपटारा 7 दिनों के अन्दर हो जाएगा।'

सेन्टर द्वार शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही की सुवना भी दी जाएगी। इससे पुलिसकर्मियों की कीमती समय में बचत होगी जिहें छोटी-छोटी बार्तों के लिए मुख्यालयों में भागना पड़ता था। कलेक्टर श्री कृष्ण ने इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पुलिसकर्मियों को मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने तहसील स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार के हेल्पलाईन की शुरुआत करने के बारे में बताया। आशा है, पुलिसकर्मियों को अपनी शिकायतों पर कार्यवाही करवाने में इस हेल्पलाईन से काफी मदद मिलेगी। हो सकता है, जल्दी ही

सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान सेवा शुरू हो जाए।

VkfstU; % n VkbE1 vklD bFM; k MKW bFM; k VkbE1 MKW dklt 27 tylbz/2012%

djsy es | Lkh i pk; rkds ds fy, Fkkuk

राज्य गृहमंत्री के अनुसार सभी पंचायतों में थाने की स्थापना करने का प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि इसके साथ ही थानों, सर्कल और सब डिवीजनों की सीमा रेखा को दोबारा बनाए जाने की मांग की गई। उन्होंने जुलाई के अंतिम सप्ताह में केरल पुलिस अफसरों की एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए बताया कि सरकार थानों, सर्कलों और सब डिवीजन की क्षेत्र सीमा को दोहराने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। सरकार सिद्धांत के स्तर पर एसोसिएशन के कानून -व्यवस्था और जांच करने वाली पुलिस को अलग करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही, कुछ थानों में लागू 8 घण्टों की शिप्ट व्यवस्था को फण्ड की उपलब्धता के आधार पर, भर्ती के अनुसार दूसरे थानों में भी बढ़ाया जाएगा। एसोसिएशन द्वारा तैयार किये गये 43 बिन्दुओं के एक डिमांड चार्टर को मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें से कई मुहूं पर चर्चा हुई। इसमें मांगी गई चौथे ग्रेड के पुलिसकर्मियों की पदोन्नति की बात पर उन्होंने कहा कि वे वित्त मंत्रालय से इसके कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करेंगे। उनके अनुसार 'सरकार पदोन्नति में विलब न हो यह कोशिश भी करेगी।' इस दौरान जहाँ उन्होंने पुलिसिंग के अहम मुद्दों पर अपनी सहमति दी वहाँ पुलिसकर्मियों को उनके संविधान और कानून द्वारा दिए गए कर्तव्यों को पूरा करने, अपराधियों पर नियंत्रण करने और प्रजातंत्र को मजबूती देने वालों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी की भी याद दिलाई। नैतिक पुलिसिंग करके कानून को अपने हांथ में लेने वालों के साथ अपराधियों के जैसे ही व्यवहार करने की नसीहत भी दी। इसके अलावा प्रत्येक पुलिसकर्मी की सुरक्षा को सरकार का दायित्व बताया।

VkfstU; % fgUhMKW dklt 29 tylbz/2012%

